भारत में विकसित होंगे हाइड्रोजन राजमार्ग

गडकरी ने कहा- 2050 तक 3 .6 गीगाटन कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना

नई दिल्ली, 26 सितंबर. भारत सरकार ने देश को ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने आज भारत के पहले हाइड्रोजन हाईवे की शुरुआत की घोषणा की. यह घोषणा एसएंडपी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स द्वारा आयोजित पहले वर्ल्ड हाइड्रोजन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे दिन की गई.

10 मार्गों पर होगा ट्रायल- गडकरी ने वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं और ऊर्जा विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए कहा कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है. उन्होंने बताया कि भारत में बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ट्रकों का परीक्षण शुरू किया जा रहा है. इस ट्रायल के लिए 10 मार्गों पर 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें 37 वाहन शामिल होंगे. इन परीक्षणों में टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वोल्वो, बीपीसीएल, एनटीपीसी और रिलायंस जैसे प्रमुख उद्योग भागीदार हिस्सा ले रहे हैं.

इन मार्गों में ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा, भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, वडोदरा, सूरत, साहिबाबाद, फरीदाबाद, पुणे, मुंबई, जमशेदपुर, कलिंगा, तिरुवनंतपुरम, जामनगर, अहमदाबाद और कोच्चि-विशाखापट्टनम शामिल हैं. इन मार्गों को भारत के पहले हाइड्रोजन हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि स्वच्छ और लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो सके.

ऊर्जा हब बनेगा कृषि क्षेत्र- गडकरी ने भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जो वर्तमान में 87% है और सालाना लगभग 22 लाख करोड़ रुपये का खर्च आता है. उन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र को ऊर्जा का पावरहाउस बनाने की अपनी दृष्टि को भी रेखांकित किया.

अमिताभ कांत ने भी दिया जोर

इस अवसर पर नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए स्थिरता को केंद्र में रखना होगा . उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ एक ऊर्जा कहानी नहीं है, बल्कि यह नौकरियों, निर्यात, विनिर्माण और जलवायु नेतृत्व के बारे में है .

रुपया गिरावट से उबरा

नई दिल्ली 26 सितंबर. अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में प्रगति की उम्मीदों के चलते शुक्रवार को भारतीय रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर से उबर गया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 6 पैसे की मजबूती के साथ 88.70 पर पहुंचा. इससे पहले गुरुवार को यह 88.76 के नए रिकॉर्ड लो पर बंद हुआ था. हालांकि एफआईआई निकासी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने रुपए की मजबूती को सीमित कर दिया. अब निवेशकों की निगाहें आगामी 1 अक्टूबर को आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक पर टिकी हैं, जहां ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है. शुक्रवार को भारतीय मुद्रा ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मामूली मजबूती दिखाई और 6 पैसे बढ़कर 88.70 पर पहुंच गई.

भारत और अमेरिका की वार्ता सकारात्मक

नई दिल्ली, 26 सितंबर. भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए एक उच्च-स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि यह दौरा काफी सकारात्मक और रचनात्मक रहा.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में गए इस प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर जैसे वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. 22 से 24 सितंबर 2025 तक चली इन चर्चाओं में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया.

मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्ष एक ऐसे व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सहमत हुए जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो. मंत्रालय ने कहा, प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी सरकार के साथ सौदे के विभिन्न पहलुओं पर रचनात्मक बैठकें कीं. दोनों पक्षों ने सौदे की संभावित रूपरेखा पर विचारों का आदान-प्रदान किया और एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के शीघ्र निष्कर्ष के लिए जुड़ाव जारी रखने का निर्णय लिया.

सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के अलावा, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका स्थित

> पिछले कुछ महीनों से, भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं . गौरतलब है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जुलाई में भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की थी, और बाद में रूस से तेल आयात के मुद्दे पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया . भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने की अमेरिकी मांग पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं, क्योंकि ये क्षेत्र भारत में लाखों लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं .

भारत की रूसी तेल रणनीति से क्रूड ऑयल स्थिर

भारत का रोजाना आयात लगभग 1.50 मिलियन बैरल

रूस से निरंतर आपूर्ति से घरेलू ऊर्जा सस्ती

मुंबई, 26 सितंबर. ब्रेंट क्रूड की कीमतें 67-69 डॉलर प्रति बैरल के बीच स्थिर बनी हुई हैं, और इसके पीछे भारत की रूसी तेल खरीद की अहम भूमिका है. वैश्विक बाजार में कीमतों को प्रभावित करने वाला कोई नया कारक नहीं है, जिससे आयातक देशों को राहत मिली है.

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, जिसकी वर्तमान आयात क्षमता लगभग 1.50 मिलियन बैरल प्रति दिन है. देश की पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना है, और रूस से लगातार आपूर्ति इस लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. रिपोर्ट में कहा गया कि आगे चलकर अमेरिका की प्रतिबंध और टैरिफ नीति ही कीमतों में उतार-चढ़ाव ला सकती हैं.

ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता- रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और चीन दोनों द्वारा रूस से बड़े पैमाने पर तेल आयात करने से, तेल की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है.

भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर अमेरिकी विचार

इस बीच, अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने भारत को एक फ़शानदार सहयोगीफ़ बताया और कहा कि वह भारत के फ़बहुत बड़े प्रशंसकफ़ हैं . न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राइट ने भारत को एक गतिशील समाज और तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग वाले देश के रूप में सराहा . उन्होंने कहा कि उनका शुरुआती समय भारत से जुड़े मामलों को देखने में बीता, और वह भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से बेहद प्रभावित हैं .

एनबीसीसी की 65वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित

नई दिल्ली, 26 सितंबर. राज्य स्वामित्व वाली नवरत्न उद्यम कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड सरकार द्वारा अवसंरचना विकास पर दिए जाने वाले अत्यधिक बल का लाभ उठाने हेतु तैयार है. श्री के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी लिमिटेड ने दिनांक 24.09.2025 को ईस्ट किदवई नगर में आयोजित 65वीं वार्षिक आम बैठक में वित्त वर्ष 24-25 के दौरान कंपनी की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला. उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में कंपनी द्वारा प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे विभिन्न अवसरों को भी प्रदर्शित किया.

बैठक के दौरान, एनबीसीसी बोर्ड के अन्य सदस्य अर्थात श्री सलीम अहमद, निदेशक (परियोजनाएं); सुमन कुमार, निदेशक (वाणिज्य); अंजीव कुमार जैन, निदेशक (वित्त); सरकार द्वारा नामित निदेशक संजीत, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार; रवि कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव (भूमि एवं संपदा) और स्वतंत्र निदेशक भीमराव पांडा भोसले, दीपक सिंह, राजीव कुमार, विशाल पुरी और श्रीमती दीप्ति गंभीर, कंपनी सचिव, एनबीसीसी भी उपस्थित रहे. कंपनी ने वर्ष-दर-वर्ष 15.68% वृद्धि के साथ 12,038.57 करोड़ रुपये का समेकित राजस्व तथा 34.52त्न की वृद्धि के साथ 557.42 करोड़ रुपये का समेकित कर-पश्चात लाभ अर्जित किया. एकल आधार पर, राजस्व 8,725.36 करोड़ रुपये रहा, जबकि कर पश्चात लाभ 38.26% बढ़कर 476.11

> महादेवास्वामी ने शेयरधारकों को संबोधित करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला तथा उनके भाषण में निम्नलिखित मुख्य बिंदु शामिल रहे . एनबीसीसी ने 180 .90 करोड़ का अपना अब तक का सर्वाधिक लाभांश घोषित किया तथा 1-2 के अनुपात में 90 करोड़ बोनस इक्विटी शेयर जारी किए, जो शेयरधारक मूल्य सृजन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है . कंपनी ने 23,250 करोड़ मूल्य के नए कार्य प्राप्त किए और अपनी प्रमुख पुनर्विकास परियोजनाओं - वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर (13,409 करोड़) और डाउनटाउन, सरोजिनी नगर (1,391 करोड़) में पूर्ण वाणिज्यिक बिक्री प्राप्त की, जो कुल मिलाकर लगभग 14,800 करोड़ है .

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट जारी

800 अंक से गिरा सेंसेक्स

250 अंक से लुढ़का निफ्टी

नई दिल्ली, 26 सितंबर. शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखी जा रही है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं के आयात पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की है. इससे खासकर फार्मा शेयरों में भारी गिरावट आई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी गिरावट आई. ट्रंप ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं के आयात पर 1 अक्टूबर, 2025 से 100 प्रतिशत तक का भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है. इससे फार्मा शेयरों में भारी गिरावट आई. बीएसई सेंसेक्स 800 अंक से ज्यादा गिरकर 80,400 के स्तर से नीचे चला गया. वहीं, निफ्टी50 भी 250 अंक से ज्यादा गिरकर 24,650 के स्तर से नीचे आ गया. दोपहर बाद 2.30 बजे सेंसेक्स 786.52 अंक यानी 0.97त्न की गिरावट के साथ 80,373.16 अंक पर था.

चांदी के भाव हुए बेकाबू सोना हुआ और सस्ता

नई दिल्ली, 26 सितंबर. सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों की चाल अलग-अलग रही. जहां सोने के दामों में हल्की गिरावट देखी गई, वहीं चांदी ने जबरदस्त तेजी दिखाई और 1.41 लाख प्रति किलो के पार पहुंच गई.

चांदी 427 की बढ़त के साथ 137467 रुपये प्रति किलो पर खुली और जीएसटी समेत इसका भाव 141591 प्रति किलो पर पहुंच गया. दूसरी ओर, 24 कैरेट गोल्ड 50 टूटकर बिना जीएसटी 113299 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला और जीएसटी जोड़ने के बाद यह 116697 हो गया. गुरुवार को इसका बंद भाव 113349 था. यानी सोने में गिरावट का सिलसिला फिलहाल जारी है. अब तक सोना 10,911 प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है.

स्पाइसजेट लीज पर लेगी एक ए340 विमान

नयी दिल्ली, 26 सितंबर. किफायती विमान सेवा कंपनी स्पाइसजेट अपनी बेड़ा विस्तार की योजना को आगे बढ़ाते हुए इसी महीने एक वाइड-बॉडी एयरबस ए340 विमान वेट लीज पर लेगी. वेट लीज में विमान के साथ पायलट और केबिन क्रू भी लीज पर विमान देने वाली कंपनी के ही होते हैं. विमान के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी भी उसी की होगी. कंपनी ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह लीज समझौता एयरलाइन की विस्तार रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

इंडिगो और एसबीआई कार्ड ने पेश किया को-ब्रांडेड

नयी दिल्ली, 26 सितंबर. विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी में गुरुवार को को-ब्रांडेड इंडिगो एसबीआई कार्ड पेश करने की घोषणा की. यह प्रीमियम क्रेडिट कार्ड दो वेरिएंट, इंडिगो एसबीआई कार्ड और इंडिगो एसबीआई कार्ड एलीट में लॉन्च किया गया है.

ग्राहकों को इंडिगो के इकोसिस्टम के अंतर्गत आने वाले सभी ऑफर, होटल और यात्रा बुकिंग सहित अन्य श्रेणियों पर किये गये सभी खर्चों पर रिवॉर्ड प्वाइंट मिलेंगे. इंडिगो के टिकट

बुक कराने या उसके साझेदारों से साथ होटल बुकिंग आदि पर इंडिगो एसबीआई कार्ड एलीट के माध्यम से खर्च करने पर सात प्रतिशत और इंडिगो एसबीआई कार्ड का उपयोग करके खरीदारी पर तीन प्रतिशत रिवॉर्ड मिलेगा. इंडिगो इकोसिस्टम से बाहर अन्य प्लेटफॉर्म पर होटल और यात्रा बुकिंग के लिए इंडिगो एसबीआई कार्ड एलीट के धारकों को तीन प्रतिशत और इंडिगो एसबीआई कार्ड के उपयोगकर्ताओं को दो प्रतिशत रिवॉर्ड मिलेगा. अन्य सभी श्रेणियों में खर्च के लिए क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत रिवॉर्ड मिलेगा. ये रिवॉर्ड इंडिगो ब्लूचिप्स के रूप में होंगे. कार्डधारक इन्हें इंडिगो की सेवाओं जैसे फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, सीट अपग्रेड, भोजन और फास्ट फॉरवर्ड जैसी सेवाओं के वाउचर आदि के माध्यम से भुना सकते हैं.

समाचार विशेष

भूपेंद्र हुड्डा हटेंगे पीछे सैलजा होंगी शांत

चंडीगढ़. बिहार में 85 साल बाद कांग्रेस सीडब्ल्यूडी की बैठक करके बड़ा दांव खेला है. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राहुल गांधी के दिल्ली लौटने के बाद अगले कुछ दिनों में हरियाणा का फंसा पेच भी खत्म हो जाएगा. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली से करीब वाले इस राज्य में संगठन के लिए नए कैप्टन को तय कर लिया है.

कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो वहीं हरियाण के दो बार मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं. राव नरेंद्र सिंह अहीरवाल से ताल्लुक रखते हैं. कांग्रेस ने पिछले साल विधानसभा चुनाव उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में लड़ा था.

अभी राव आरती सिंह हैं मंत्री-अहीरवाल में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा प्रभाव माना जाता है. यही वजह है कि बीजेपी ने 75 पार के बाद भी उन्हें मंत्री बनाकर साधा हुआ है. इसके साथ उनकी बेटी आरती राव हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं. अगर राव नरेंद्र की ताजपोशी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर होती है तो निश्चित तौर पर अहीरवाल यानी दक्षिण हरियाणा की राजनीति गरमाएगी. इस क्षेत्र में कांग्रेस पिछले कुछ सालों में कमजोर हुई हैं.

राव नरेंद्र के बागडोर संभालने पर पार्टी को राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह की के बीच अपना स्पेस बढ़ाने का मौका मिलेगा. अभी तक इस क्षेत्र में कांग्रेस कैप्टन अजय सिंह यादव को तवज्जो देती आई है. सूत्रों का कहना है राहुल गांधी हरियाणा में मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी और गुजरात के अमित चावड़ा जैसा ही प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं. जो बीजेपी से आंख में आंख मिलाकर लड़ सके.

क्यों चर्चा में आया इनका नाम

हरियाणा के नए अध्यक्ष के लिए राव नरेंद्र के नाम की चर्चा दिल्ली से चंडीगढ़ तक है . उन्हें बिहार में कांग्रेस की विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक में सदस्य नहीं होने के बाद भी बैठक से पहले दिल्ली बुलाया गया था . सूत्रों की मानें की हाईकमान ने राव नरेंद्र पर दांव खेलने का मन बना लिया है . राव नरेंद्र की उम्र अभी 62 साल है . वह नारनौल के रहने वाले हैं . 2009 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे . तब वह हार गए थे . इसके बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी कुलदीप विश्नोई की पार्टी से लड़े थे . राव नरेंद्र नारनौल से जीतने से सफल रहे थे .

धर्मेंद्र तोड़ेंगे राहुल-तेजस्वी का चक्रव्यूह

नई दिल्ली. बिहार में भले ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर कर दी है. बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभारी और सह-प्रभारी के नामों की घोषणा की है. भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि गुजरात बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सीआर पाटिल और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति बिहार में एनडीए की मजबूती को बढ़ावा देने के लिए अहम मानी जा रही है. साथ ही पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे अहम सियासी राज्यों के लिए भी चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की गई है.

इन दिग्गजों को मिली अन्य राज्यों की जिम्मेदारी- पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि सह-प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब होंगे. पश्चिम बंगाल में टीएमसी की मजबूत पकड़ को तोड़ने के लिए बीजेपी की यह रणनीति अहम मानी जा रही है. 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं. तमिलनाडु के लिए ओडिशा से सांसद बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि महाराष्ट्र से सांसद मुरलीधर मोहोल सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है. तमिलनाडु में भी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं.

> **महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकतें हैं धर्मेंद्र प्रधान**
>
> बताया जा रहा है कि, बीजेपी के लिए धर्मेंद्र प्रधान का चयन इसलिए अहम माना जा रहा है कि, क्योंकि वे पहले भी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं . धर्मेंद्र प्रधान की रणनीतिक क्षमता और संगठनात्मक कौशल बिहार में तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को चुनौती देने में कारगर साबित होगा . बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्राओं से माहौल थोड़ा बदला है .

उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम पीडीए

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं. लोकसभा चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन के बाद अब राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपने स्वजातीय लोगों पर मेहरबानी का बड़ा मुद्दा बना है.

भाजपा की विरोधी पार्टियां तो यह मुद्दा उठा ही रही हैं, पार्टी के अंदर भी लोग इसे लेकर मुखर होने लगे हैं. पिछले कुछ दिनों से इस पर ज्यादा फोकस बना है. राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी इसे लेकर बहुत मुखर है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद कई नियुक्तियों के बारे में विस्तार से सोशल मीडिया में लिखा. उन्होंने राजपूत बनाम पीडीए का अंतर दिखाया है.

गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पीडीए यानी पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक का समीकरण बनाया है. इसका लाभ उनको लोकसभा चुनाव में मिली. समाजवादी पार्टी राज्य में सबसे ज्यादा सीटों पर जीती. तभी अखिलेश यादव ने ठाकुर बनाम पीडीए का माहौल बनाया है. अखिलेश ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 नियुक्तियां हुईं, जिनमें से 15 ठाकुर यानी राजपूत समाज के हैं और पीडीए के सिर्फ आठ हैं.

विशेष | **राजनीति में पकड़ बनाना प्राथमिकता**

बहुजन समीकरण पर बसपा की नजर

पटना. बिहार में चुनाव लोकसभा के हो या फिर विधानसभा के जातिगत समीकरण हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं. दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ अति पिछड़ा, और अल्पसंख्यक मतदाता यहां हार-जीत की कहानी गढ़ते हैं. यही वह आधार है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बना रही है.

पिछले दिनों बसपा प्रमुख मायावती ने स्वयं यह खुलासा किया कि उनकी पार्टी बसपा बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार

खड़े करेगी. इतना ही नहीं बिहार में लगातार चुनावी राजनीति में पराजित रहने वाली बसपा ने इस चुनाव बड़ी घोषणा की है कि पार्टी सर्वाधिक टिकटें दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रत्याशियों को देगी. इस निर्णय के पीछे उसकी सोची-समझी रणनीति है. उसका मानना है इन वर्गों को एकजुट कर लिया जाए तो चुनावी राजनीति में बिहार जैसे प्रदेश में बढ़त बनाई जा सकती है. मायावती का अनुभव उत्तर प्रदेश में इसी समीकरण को साधने का रहा है और अब वही फार्मूला बिहार की धरती पर आजमाने की तैयारी है.

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार की मौजूदा राजनीति एनडीए और महागठबंधन के बीच बंटी हुई है, लेकिन बहुजन राजनीति में घुसपैठ की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है. कांग्रेस, राजद और जदयू जैसी पार्टियां भले ही सामाजिक न्याय की राजनीति का दावा करती हों, परंतु इन वर्गों को संपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं दे पाई है. ऐसे में बसपा इस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही है.

सूत्रों की माने तो बसपा का फोकस सिर्फ टिकट बंटवारे पर ही नहीं, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने पर भी है. दलित और अति पिछड़े समुदायों में छोटे-छोटे उपजातीय समीकरणों को साधने के लिए पार्टी गांव-गांव तक पैठ बनाने में जुटी है.

> **बिखरे वोटों को एकजुट करना आसान नहीं**
>
> मायावती के करीबी नेताओं का मानना है कि अगर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यकों का एक हिस्सा ही बसपा के साथ खड़ा हो गया, तो बिहार की राजनीति में नया समीकरण उभर सकता है . हालांकि बसपा की सोच और हकीकत में चुनौतियां भी कम नहीं . बड़ी चुनौती यह है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों का वोट बंटा हुआ है . राजद का आधार पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय रहा है, वहीं जदयू ने अति पिछड़ों पर पकड़ बनाई है . कांग्रेस भी इन्हीं समुदायों पर अपनी राजनीति केंद्रित कर रही है . दलितों में रामविलास पासवान की विरासत का असर अब भी लोक जनशक्ति पार्टी में देखा जाता है . ऐसे में बसपा के लिए इन बिखरे वोटों को एकजुट करना आसान नहीं होगा .